उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

**देहरादून 17 मार्च, 2018(सू.ब्यूरो)** **प्रेस नोट–08(03/69)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत रविवार 18 मार्च, 2018 को परेड ग्राउण्ड, देहरादून में अपराह्न 02.00 बजे उत्तराखण्ड सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में नवनियुक्त डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ आशा कार्यकत्रियों को मानदेय का वितरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को सस्ता ऋण, ओ.डी.एफ. घोषित हो चुके निकायों को प्रमाण पत्र, लाभार्थियों को ई–रिक्शा, उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन एवं दुग्ध उत्पादकों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जाएंगे।

कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जनोपयोगी स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस अवसर पर माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण एवं माननीय विधायकगण भी प्रतिभाग करेंगे।

***सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।***

**नई दिल्ली/देहरादून 17 मार्च, 2018(सू.ब्यूरो)** **प्रेस नोट–07(03/68)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट से भेंट कर उनकी कुशलछेम पूछी। उन्होंने श्री बिष्ट के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से श्री बिष्ट के उपचार के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की।

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अजय भट्ट भी उपस्थित थे।

**नई दिल्ली/देहरादून 17 मार्च, 2018(सू.ब्यूरो)** **प्रेस नोट–06(03/67)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में उपचार हेतु दिल्ली आये उत्तराखण्ड के महाधिवक्ता श्री सूर्य नारायण बाबुलकर से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने श्री बाबुलकर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

***राज्य सूचना केन्द्र नई दिल्ली से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।***

देहरादून 17 मार्च, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(03/66)

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुबर्द्धन ने बताया कि जनपद पिथौरागढ की क्षेत्र पंचायत, धारचूला के प्रमुख का पद, जो कि निर्वाचित प्रतिनिधि के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण रिक्त हो गया है, पर उप निर्वाचन कराया जाना है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि रिक्त प्रमुख के पद का नामांकन दिनांक 19.03.2018 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 03.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की जांच दिनांक 19.03.2018 को अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, नामांकन पत्रों की वापसी दिनांक 20.03.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक, मतदान दिनांक 22.03.2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 तक तथा मतगणना दिनांक 22.03.2018 को मतदान समाप्ति के तत्काल बाद शुरू की जायेगी।

उन्होंने कहा कि उक्त उप निर्वाचन कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड की अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2018 निर्गत होने के साथ ही तात्कालिक प्रभाव से जनपद पिथौरागढ़ की क्षेत्र पंचायत धारचूला में आदर्श आचार संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

*सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।*

देहरादून 17 मार्च, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(03/65)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में रिस्पना नदी के पुनरोद्धार के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि रिस्पना से ऋषिपर्णा बनाने का कार्य मिशन मोड़ में होना चाहिए। यह कार्य जन सहयोग से पूरा किया जायेगा। रिस्पना के उद्गम से संगम तक ट्रेंचेंज का कार्य एक दिन में पूर्ण किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इसकी लिए शीघ्र तिथि निर्धारित की जाये। रिस्पना नदी पर वृक्षारोपण एवं सफाई का कार्य भी जन सहयोग से जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में एक ही दिन में पूर्ण हो सके यह भी सुनिश्चित किया जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि रिस्पना के पुनर्जीवीकरण के लिए जनसहयोग लिया जायेगा। विभिन्न संस्थाओं से भी आर्थिक सहयोग लिया जायेगा। उन्होंने इसके लिए एक ट्रस्ट बनाने के लिए कहा। मिशन ऋषिपर्णा के लिए सबको तन, मन एवं धन से सहयोग करना होगा। इस मिशन में विभिन्न संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं को भी शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि रिस्पना के पुनर्जीवीकरण के लिए बनाये गये सेक्टरों को सब सेक्टरों में भी विभाजित किया जाय। ताकि सब सेक्टर वाइज वृक्षारोपण, सफाई एवं ट्रेंचेज बनाने का टारगेट पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए कम से कम 25 हजार लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना नदी पर विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष लगाये जायें। जिसमें फलदार वृक्ष, चारा प्रजाति के वृक्ष एवं नेपियर घास की प्रजाति को प्राथमिकता दी जाय। उन्होंने कहा कि इस अभियान को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता लाई जाए।

बैठक में जिलाधिकारी देहरादून श्री एस.ए. मुरूगेशन ने कहा कि रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए पूरे क्षेत्र में 15 सेक्टर बनाये गये हैं। इस कार्य हेतु ईको टास्क फोर्स, वन विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, नगर निगम एवं एमडीडीए द्वारा कार्य योजना बनाई जा चुकी है।

बैठक में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून 17 मार्च, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(03/64)

## मुख्यमंत्री ने पलायन आयोग की वेबसाइट लांच की

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पलायन आयोग की वेबसाइट www.uttarakhandpalayanayog.com का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने आयोग की वेबसाइट को महत्वपूर्ण कदम बताते हुये कहा कि इससे लोगों को अपनी बात और सुझाव रखने का महत्वपूर्ण मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन आयोग अच्छा कार्य कर रहा है। आयोग द्वारा प्रदेश में शत–प्रतिशत सर्वेक्षण किया जा चुका है। कई लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन की इच्छा जाहिर की है। पर्वतीय क्षेत्रों में खाली भूमि उपयोग हेतु कई लोगों ने ऑफर किया है।

## पलायन आयोग की पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल तक

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पलायन आयोग की पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल तक शासन में आ जायेगी। इस रिपोर्ट में पलायन के विभिन्न आयामों एवं पलायन की गम्भीरता से सम्बन्धित आंकड़ों का अध्ययन होगा।

पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस.एस.नेगी ने बताया कि वेबसाइट से लोगों के सुझाव प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा प्रदेश के सभी गावों में शत–प्रतिशत सर्वे कर लिया गया है। सर्वे में ग्रामवासियों के पलायन से संबन्धित विभिन्न तथ्यों पर जानकारी जुटाई गई है। श्री नेगी ने बताया कि सर्वे के दौरान कई गावों में रिवर्स माइग्रेशन भी सामने आई है। कई गावों में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी भी मिली है। जिन्हे प्रदेश के अन्य भागों हेतु मॉडल बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आयोग का कार्यालय पौड़ी के ग्राम्य विकास विभाग के भवन में काम कर रहा है। और अप्रैल प्रथम सप्ताह में अपने स्वयं के भवन में शिफ्ट हो जायेगा।

देहरादून 17 मार्च, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(03/62)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र एवं भारतीय नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएँ दी हैं। नवरात्र के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेशवासियों के लिये नववर्ष में मंगलमय एवं खुशहाल जीवन की कामना की है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परम्परा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से ही स्त्रियों के सम्मान की परम्परा रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का यह पर्व समाज में नारी के महत्व और सामर्थ्य को बताता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर किया जाने वाला कन्यापूजन नारीशक्ति के महत्व को दर्शाता है, परन्तु हमें सदैव ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं को और सशक्त बनाने के लिए 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लें।

*सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।*

देहरादून 17 मार्च, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(03/63)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर प्रदेश वासियों का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से राज्य की सेवा का अवसर दिया। पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार ने उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए समाज के हर वर्ग का उत्थान करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। किसान, महिला और गांव सरकार की नीतियों के केंद्र में हैं। पहाड़ से पलायन रोकना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताएं हैं। मात्र कोरी घोषणाएँ नहीं की गयी हैं, बल्कि ऐसी घोषणाएं की गयी हैं, जिन्हें पूरा किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि विकास की दृष्टि से उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो, इसके लिये राज्यहित में अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। हमारा प्रयास योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन का है। समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिये समेकित प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 168 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी हुयी है। परिवहन विभाग के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 140 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी हुयी है। खनन विभाग में ई–ऑक्शन प्रक्रिया लागू करने के बाद राजस्व में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की है।

पी.डब्ल्यू.डी. के चालू निर्माण कार्यों हेतु बीते साल के रू. 420 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष 630 करोड़ रूपये का कार्य किया गया है। पिछले एक वर्ष में कुल 1754 किमी लम्बाई की नई सड़कों एवं 57 पुलों का निर्माण एवं 567 किमी लम्बाई की सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया। सड़कों एवं पुलों से 83 गांवों एवं 250 से अधिक की जनसंख्या की 198 बसावटों को भी जोड़ा गया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य के 99.60 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हो गये हैं। विगत एक वर्ष में 51 दूरस्थ गाँव विद्युतीकृत किए गए एवं शेष 21 गाँव मार्च के अन्त तक विद्युतीकृत हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष में 552 नई बस्तियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है। 572 नये स्थानों पर हैण्डपम्प लगाए गए हैं। 1273 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार किया गया है। प्रदेश में 3837 चाल–खाल, जलकुण्ड, फार्म पॉण्ड का निर्माण किया गया है। देहरादून में सूर्यधार झील परियोजना का कार्य शुरू हो गया है। देहरादून में रिस्पना नदी व अल्मोड़ा में कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु अभियान प्रारम्भ हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में लगभग 600 अतिरिक्त चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त किया गया। इनमें 239 बॉन्डधारी चिकित्सकों की भी नियुक्ति भी सम्मिलित हैं। मैदानी क्षेत्रों में सुविधा जनक स्थानों पर वर्षों से जमें डाक्टरों की संबद्धता समाप्त कर उन्हें वापस मूल स्थानों पर तैनात किया गया है। राज्य के दूरस्थ अस्पतालों में 149 दंत चिकित्सकों की भी तैनाती की गयी है। 481 चिकित्सकों एवं 293 स्वास्थ्य कार्यकत्रियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। राज्य में 22 प्रमुख अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है, अन्य 13 अस्पतालों में शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के 4 स्वास्थ्य केन्द्रों (अगस्त्यमुनि, भिकियासैंण, नौगांव एवं ओखल काण्डा) में ई–हेल्थ सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन ई–हेल्थ सेंटर्स पर 60–65 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राज्य के 47 अस्पतालों में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारम्भ की गयी है। सरकार द्वारा आशा कार्यकत्रियों के लिये वर्ष 2012 से रूकी हुई 33 करोड रूपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी कर दी गयी है। आशा कार्यकत्रियों तथा ए.एन.एम. के लिये रू0 2 लाख की दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गयी है और सभी ए.एन.एम. के लिये कम्प्यूटर टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी सरकार प्रयासरत् है। 15 ग्रॉथ सेंटरों में महिलाओं को एल.ई.डी. उपकरण निर्माण की ट्रेनिंग दी जा रही है। सामाजिक रूप से कमजोर एवं निराश्रित महिलाओं के लिये एक लाख तक ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। एकल महिलाओं के लिये सखी ई–रिक्शा योजना शुरू की गयी है। इसके साथ ही प्रथम स्पर्श सैनेटरी नैपकिन उत्पादक इकाई शुरू कर दी गयी है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने हेतु शुरू की गयी योजना के अन्तर्गत अब तक सवा लाख से अधिक किसानों को लगभग 600 करोड रूपये का ऋण मात्र 02 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा चुका है। पर्वतीय क्षेत्र में छोटी एवं बिखरी जोतों की चकबन्दी का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 1131 आधुनिक मिल्क कलेक्शन यूनिटों की भी स्थापना की गयी है। आधुनिक मिल्क कलेक्शन यूनिटों की स्थापना से किसान को दुग्ध विक्रय से औसतन 6 रूपये प्रति लीटर तक की अतिरिक्त आमदनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट कम्पोनेंट में देश का पहला प्रशिक्षण केन्द्र उत्तराखण्ड में खोला गया है। एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में 2951 ईकाइयों की स्थापना की गयी है, जिससे लगभग 17 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य में सेण्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी के लिये भवन एवं भूमि चिन्हित कर ली गयी है, जिसमें इस वर्ष से कक्षाओं की शुरूआत कर दी जाएगी।

सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत लगभग 2500 करोड रूपये के 460 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। नई स्टार्ट अप नीति–2018 भी लागू कर दी गयी है। उद्यमियों को नये उद्यमों हेतु भूमि खरीदने की अनुमति अब जिला स्तर से ही प्राप्त हो जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के विकास के लिये रोडमैप निर्धारित करते हुए हमने लक्ष्य 2020 के अन्तगर्त 2020 तक राज्य की सभी योजनाओं में डीबीटी लागू करने, राजस्व दोगुना करने, 05 हजार होम स्टे का निमार्ण, 01 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने, 200 स्टार्ट अप आरम्भ करने, 04 लाख 35 हजार वंचित परिवारों में से कम से कम एक व्यक्ति प्रति परिवार को जीविका के साधन देने, सर्विस सेक्टर में 01 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने, सभी ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाईबर कनेक्टिविटी देने जैसे लक्ष्य रखे है।

*सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।*